



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 10 अप्रैल, 1997/20 चैत्र, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 10 अप्रैल, 1997

संख्या विधायन/बिल/1-27/97-वि0 स0—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक

1997 (1997 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 10 अप्रैल, 1997 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

1997 का विधेयक संख्यांक 12.

उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1997

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1997 है ।

1971 का 5

2. उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 5 का प्रतिस्थापन ।

“5. उप-मन्त्रियों के निवास स्थान.—(1) प्रत्येक उप-मन्त्री को, एक निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर उसे दो हजार पांच सौ रुपये प्रति मास की दर से भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, उप-मन्त्री को दिए गए गृह का उसे, उसके उप-मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए, निःशुल्क अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण.—उप-मन्त्री ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आवंटित गृह का मंगक किराया उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।” ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1997 के अधिनियम संख्यांक 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित, उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) की धारा 5 के विद्यमान उपबन्ध, संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के भाव के विरुद्ध हैं। अतः उक्त उपबन्धों को संविधान के उपबन्धों के समरूप बनाने के लिए, यथोचित संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला:

10 अप्रैल, 1997.

द्वितीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से अतिरिक्त आवर्ती खर्च होगा। वर्तमानतः मन्त्री का कोई पद नहीं है, अतः अन्तर्वर्तित वास्तविक खर्च का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
[सामान्य प्रशासन विभाग नस्ति संख्या जी0ए0डी0-सी (पीए) 4-23/94]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1997 विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक विधान सभा में पर-स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 1997.

**THE SALARIES AND ALLOWANCES OF DEPUTY MINISTERS
(HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 1997**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Salaries and Allowances of Deputy Ministers
(Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1997.

Short title.

2. For section 5 of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971, the following shall be substituted, namely:—

Substitution of section 5.

“5. Residence of Deputy Ministers.—(1) Each Deputy Minister shall be provided with a free furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at the rate of two thousand and five hundred rupees per mensem.

(2) The State Government may allow a Deputy Minister to continue in free occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Deputy Minister.

Explanation.—The Deputy Minister shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified in sub-section (1).”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Existing provisions of section 5 of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971), as substituted *vide* Act No. 2 of 1997, are against the spirit of the provisions contained in clause (5) of article 164 of the Constitution. Thus in order to bring the said provisions in conformity with the provisions of the Constitution it has become necessary to make suitable amendments.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 10th April, 1997.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer. At present there is no office of Deputy Minister, as such the actual expenditure involved can not be anticipated.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C (PA) 4-23/94]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 1997, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.